



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219620
CG-DL-E-28052020-219620

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1502]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942

No. 1502]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISHTHA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

का.आ. 1672(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 4क के उप-नियम (1) के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का निरसन करने और इसे दो संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के पश्चात, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय सशक्त समिति के पुनर्गठन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1025(अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, क्रम सं. (ग) के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः—

(घ) जम्मू और कश्मीर का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनः

(i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफसीए), संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जम्मू और कश्मीर;

(ii) प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, सिविल सचिवालय, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जम्मू और कश्मीर।

(ड.) लद्दाख का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन:

- (i) मुख्य वन संरक्षक (एफसीए), वन विभाग, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (लद्दाख);
- (ii) उप सचिव, राजस्व विभाग, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (लद्दाख)।

[फा. सं. 6-22 / 2014-आरओएचक्यू]

अंजन कुमार मोहंती, वन महानिदेशक (एफसी)

टिप्पण: इसे भारत के राजपत्र में सं. 4-7/2012-आरओएचक्यू, दिनांक 8 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित संकल्प के पैरा (2) क्रं सं. 5 में सारणी घ के साथ पढ़ा जाए, जहां क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का कार्य क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के रूप में उल्लिखित है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**(Regional Offices Headquarters Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2020

S.O. 1672(E).— In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003, the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1025(E), dated the 25th February, 2019 for reconstitution of Regional Empowered Committee at Regional Office, Northern Zone, Chandigarh, after abrogation of Article 370 of Jammu & Kashmir on 05th August, 2019 and bifurcating it into two Union Territories namely Jammu & Kashmir and Ladakh, namely:-

2. In the said notification, in the paragraph 2., after serial No. (C), the following shall be inserted, namely:-

(D) Union Territory Administration of Jammu and Kashmir:

- (i) Additional Principal Chief Conservator of Forests (FCA), Union Territory Administration, Jammu & Kashmir;
- (ii) Principal Secretary, Revenue Department, Civil Secretariat, Union Territory Administration, Jammu & Kashmir.

(E) Union Territory Administration of Ladakh:

- (i) Chief Conservator of Forests (FCA), Forest Department, Union Territory Administration, Ladakh;
- (ii) Deputy Secretary, Revenue Department, Union Territory Administration, Ladakh.

[F. No. 6-22/ 2014- RoHQ]

ANJAN KUMAR MOHANTY, Inspector Genl. of Forests (FC)

Note: It may be read along-with the Resolution published in the Gazette of India, *vide* No. 4-7/2012-ROHQ dated 08th January, 2014 Para (2), D in table at serial number 5 where jurisdiction of Regional Office, Chandigarh is mentioned as Chandigarh, Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab.